

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 80/2005

दायर दिनांक— 14.10.2005

उनवान

अनिल कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र एण्डू जाति ईसाई निवासी पिपलोद तह० अटरू जिला बारां राज०।

प्रार्थी/वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तह० अटरू जिला बारां राज०।

अप्रार्थी/प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर० टी० एक्ट

बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति:—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 18/07/2022

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर०टी०एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तह० अटरू जिला बारां में आराजी पुराना ख०नं० 249 का रकबा 16 बीघा, ख०नं० 294 का रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा तथा ख०नं० 544 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी को खातेदार बेन्जिमन द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी के नामान्तरण संख्या 376 से खाते दर्ज हुई थी। उक्त आराजी वादी के अपने दादाजी के जीवनकाल से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाद पत्र के मद नं० 1 में वर्णित आराजीयात ख०नं० 249 का रकबा 16 बीघा को दोराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नवीन ख०नं० 232 का रकबा 2.22 है० बनाया है। जो पुराने रकबे से 2 बीघा 1 बिस्वा के लगभग कम है। अर्थात् सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय वादी के खाते में 0.33 है० के लगभग आराजी कम कर दी गई है। यह गलती सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो काबिल दुरुस्ती है। वादी ने वाद पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दी नवीन जमाबन्दी पुराना नक्शा मिलान क्षेत्रफल, नवीन नक्शा पेश किया है जो काबिल गौर है। वादी सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद के माध्यम से इन्द्राज दुरुस्त करवाकर यह घोषणा

करा पाने का अधिकारी है कि वादी के खाते में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया कम रकबा 0.33 है0 आराजी का नवीन ख0नं0 व नवीन नक्शा कायम किया जाकर 0.33 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज करते हुये वादी को 0.33 है0 आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। मौके पर तो वादी सम्पूर्ण रकबा 16 बीघा पर काबिज है लेकिन यह कमी सेटलमेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की है। वादी को अपने खाते में कम हुये रकबे की जानकारी दिनांक 05.04.2005 को हल्का पटवारी द्वारा नवीन सेटलमेन्ट जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रथम बार हुई। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर महोदय बारां को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। वादी उक्त वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पेश किया जा रहा है। अतः वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई नियमित रूप से की जावे। सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता का नाम एण्ड के स्थान पर हेण्डू कर दिया है। इसको भी दुरुस्त करके वादी के पिता का नाम ऐण्डू किया जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक दावा हाजा पेश है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी पारित की जावे कि—

(अ) इन्द्राज दुरुस्त करते हुये वादी के खाते में कम हुआ रकबा 0.33 है0 का नवीन ख0नं0 व नक्शा बनाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे। उक्त रकबे पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा पिता के नाम पर हेण्डू की जगह एण्डू दर्ज किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 1 के तथ्य स्वीकार है। बिन्दु संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा उस ख0नं0 का

उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें प्रार्थी की कम की गई 0.35 है० भूमि शामिल की गई है। बिन्दु संख्या 4 प्रार्थी वर्तमान में जितनी भूमि तक का खातेदार है उस सीमा तक कब्जा स्वीकार है। बिन्दु संख्या 5 स्वीकार नहीं है। बिन्दु संख्या 6 स्वीकार नहीं है। बिन्दु संख्या 7 राजस्व रिकार्ड का अवलोकन पर प्रार्थी के पिता का ना हेण्डू की बजाय एण्डू करने पर आपत्ति नहीं है। बिन्दु संख्या 8 से 10 कानूनी है।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की—

तनकी नं. 1— आया वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख०नं० 249 का रकबा 16 बीघा था जिसका बाद सेटलमेन्ट नवीन ख०नं० 232 का रकबा 2.22 है० बनाकर 0.33 है० रकबा कम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादी पूरे रकबे पर काबिज काश्त है इस वजह से वादी कम हुआ रकबा 0.33 है० को अपने नाम खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी है—(वादी)

तनकी नं. 2— आया वादी ने उस ख०नं० का उल्लेख नहीं किया है कि कम किया हुआ रकबा किसमे शामिल किया गया है। (प्रतिवादी)

तनकी नं. 3—दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत **pw1** के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। प्रकरण में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट चाही गई, तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/1165 दिनांक 19.05.2022 को मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वादी उक्त बिन्दू में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्षियों के आधार पर स्वयं सिद्ध करें। वर्तमान जमाबन्दी के खातेदार अनिल कुमार पुत्र हेन्दु जाति इसाई के नाम ग्राम पिपलोद ख०नं० 232 रकबा 2.22 है० खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। शेष तथ्यों को वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू कानूनी है। तथा शेष तथ्यों को वादी स्वयं रिकार्ड के आधार पर सिद्ध करें। मुताबिक खसरा गिरदावरी वादी केवल अपने खातेदारी ख०नं० 232 रकबा 2.22 पर ही काबिज है। बिन्दू संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 6 कानूनी है। बिन्दू संख्या 7 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 8 कानूनी है। बिन्दू संख्या 9 कानूनी है। बिन्दू संख्या 10 कानूनी है।

विशेष कथन

वादी द्वारा अपने वाद में यह नहीं बताया कि उसका साबिक रिकॉर्ड की मुकाबले कौन-कौनसे ख०नं० में से कितना कितना रकबा कम हुआ है तथा ग्राम पिपलोद का ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० किस्म गै० मु० रास्ता सरकारी खाते में दर्ज रिकार्ड है एवं नक्शा सीट के दर्ज है जो वर्तमान में मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक बाराहमासी है और वादी के साथ साणि अन्य काश्तकार भी उक्त रास्ते का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में वादी को रास्ते की भूमि से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी का वाद निरस्त करना उचित होगा।

5. प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है—

तनकी नं. 1—इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि वादी के साबिक ख०नं० 249 रकबा 16 बीघा का दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा नवीन ख०नं० 232 रकबा 2.22 है० बनाकर वादी की आराजी का रकबा 0.33 है० कम कर दिया गया जिसका सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। वादी अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर आज भी 16 बीघा अर्थात् 2.55 है० भूमि पर कब्जे काश्त चला आ रहा है। अतः वादी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर रकबा 2.22 है० से बढ़ाकर 2.55 है० किया जावे और वादी को बडी हुई 0.33 है० भूमि पर खातेदार घोषित किया जावे। अभिभाषक वादी द्वारा आगे बहस करते हुए कथन किया कि वादी के खेत ख०नं० 232 से लगवा सरकारी भूमि ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग ने वादी का रकबा कम करके उक्त सरकारी भूमि का रकबा बढ़ा दिया गया है। अतः सरकार भूमि ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० में से 0.33 है० भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक वादी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट के दौरान मौके पर वास्तविक स्थिति को ध्यान रख कर ही नवीन फील्ड मेप व जमाबन्दी तैयार की जाती है और यदि किसी खसरे की स्थिति में परिवर्तन किया जाना हो तो सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा पहले उस परिवर्तन से प्रभावित पक्षकारों को कच्चा पट्टा देकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही पक्का पट्टा/भू प्रबंध

मिसल तैयार की जाती है। यदि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने वादी की आराजी का रकबा 0.33 है० कम किया था तो वादी को वक्त सेटलमेन्ट आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए थी। अतः सेटलमेन्ट के 30 वर्ष बाद वादी द्वारा पेश आपत्ति को खारिज फरमाया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा आगे कथन किया कि वादी के साबिक ख०नं० 249 के सेटलमेन्ट द्वारा केवल एक खसरा संख्या 232 नहीं बल्कि दो खसरे— ख०नं० 232 रकबा 2.22 है० एवं ख०नं० 231/1049 रकबा 0.09 है० बनाये गये है। इस प्रकार वादी की आराजी का रकबा 0.33 है० कम न करके 0.24 है० कम किया गया है। वादी का यह कथन कि समीपस्थ सरकारी भूमि ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० भूमि में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रकबा बढ़ाया गया है— अस्वीकार है क्योंकि उक्त गै०मु० रास्ते का वादी की आराजी के पास सेटलमेन्ट से पूर्व ख०नं० 264 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा था जिसका सेटलमेन्ट के बाद 0.97 है० रकबा दर्ज करने के बजाय 0.80 है० दर्ज किया गया है। उक्त रास्ता मौके पर सालभर चालू रहता है और आसपास के सैंकड़ों किसान इसी से होकर अपनी कृषि आराजी तक पहुंचते है अतः उक्त गै०मु० रास्ते का रकबा यथावत रखते हुए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी का रकबा कम किया जाना— उपरोक्त उभय पक्षकारों की बहस के आलौच्य में रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2039—42 प्रदर्श—4, भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—2, जमाबन्दी संवत 2057—60 प्रदर्श—3, मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2019 व 21.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी के साबिक ख०नं० 249 रकबा 16 बीघा के नवीन ख०नं० 232 रकबा 2.22 है० व ख०नं० 231/1049 रकबा 0.09 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.32 है० बनाकर वादी का रकबा करीब 0.24 है० कम दर्ज किया है जिसका सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को बिना किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के कोई अधिकार नहीं था।

वादी का कम हुआ रकबा कहां बढ़ाया गया— अब प्रश्न यह है कि वादी का सेटलमेन्ट कार्मिकों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान कम किया गया रकबा 0.24 है० आस पास के किस खसरे/खसरों में बढ़ाया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा पेश ग्राम पिपलोद के साबिक ख०नं० 249 के नजरी नक्शे संवत 2012 प्रदर्श—5, नवीन खसरे 232 के नजरी नक्शे व मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी

की विवादित आराजी के आस पास खेतों के साबिक ख०नं० 248, 250, 251 एवं 264 है। उक्त खेतों के साबिक ख०नं० के मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट द्वारा साबिक ख०नं० 250 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा 227 रकबा 0.66 है०, साबिक ख०नं० 248 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा का नवीन ख०नं० 231 रकबा 2.83 है०, साबिक ख०नं० 251 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का नवीन ख०नं० 233 रकबा 1.75 है० व साबिक ख०नं० 264 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के नवीन ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० दर्ज किया गया है जो कि नियमानुसार है। आस पास के उक्त खसरा नम्बरों में से किसी भी खसरा नम्बर का रकबा दौरान सेटलमेन्ट बढ़ाया नहीं गया है। इस संबध में परोकार सरकार तहसीलदार अटरू द्वारा बहस के दौरान पेश हाल मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 का भी अवलोकन किया गया जिसमें परोकार सरकार द्वारा समीपस्थ सरकारी आराजी गै०मु० रास्ता ख०नं० 235 रकबा 0.80 है० जो एक बारह मासी रास्ता है और सैंकडो काश्तकारों के लिए अपनी कृषि आराजी तक एक पहुंच मार्ग है— मे से कोई कमी नहीं करते हुए वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

यह तो स्पष्ट है कि वादी का कम हुआ रकबा किसी न किसी खसरे में जरूर बढ़ाया गया होगा क्योंकि सम्पूर्ण राजस्व ग्राम पिपलोद का सेटलमेन्ट से पूर्व एवं सेटलमेन्ट के बाद कुल रकबा समान रहना चाहिए। कम हुआ रकबा किस खसरे में बढ़ाया गया है – यह सिद्ध करने का भार वादी पर था लेकिन वादी द्वारा मौखिक साक्ष्यों के अलावा ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जो यह सिद्ध करता हो कि वादी का कम हुआ रकबा इस या इन खसरा नम्बरों में बढ़ाया गया है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 1 आंशिकतः ही वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं० 2— तनकी नं 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2039—42 प्रदर्श—4, भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—2, जमाबन्दी संवत 2057—60 प्रदर्श—3, मौका कमिश्नर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2019 व 21.10.2019, साबिक ख०नं० 249 के नजरी नक्शे संवत 2012 प्रदर्श—5, नवीन खसरे 232 के नजरी नक्शे तथा साबिक ख०नं० 248, 250, 251, व 264 के भू० प्रबंध मिलान क्षेत्रफल आदि के आधार पर एवं तनकी नं० 1 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी परोकार सरकार यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि वादी का कम हुआ रकबा किस खसरे में बढ़ा है यह

दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं हो पाया है। अतः तनकी नं0 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां